ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 10, Issue 3, March 2020 Impact Factor 5.132 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

मधुबनी में अनुसू चत जनजाति के सामाजिक-आ थक स्थिति का आंकलन

अ मत कुमार

भूगोल वभागए आर0 के0 कॉलेज मधुबनी, (बिहार)

Abstract

यह शोध पत्र व भन्न सरकारी योजनाओं के तहत बैंकों से प्राप्त वत्तीय सहायता के आलोक में मधुबनी की अनुसू चत जनजातियों की सामाजिक-आ थक स्थिति का आकलन और अध्ययन करने का प्रयास करता है। बिहार को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है और संर चत प्रश्नावली का उपयोग करके 100 परिवारों के बीच सर्वेक्षण कया गया। परिणाम से पता चलता है क अनुसू चत जनजाति के लोगों ने मुख्य रूप से कृ ष उद्देश्यों के लए सरकारी योजनाओं के तहत व भन्न वत्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की गई वत्तीय सहायता का लाभ लेना शुरू कया गया है ता क वे अपनी फसल के उत्पादन को बढ़ा सकें और अपने सामाजिक और आ थक परिस्थितियों में सुधार कर सकें। यह अध्ययन यह निष्कर्ष निकालता है क कुल मलाकर , बिहार जिले के मधुबनी में जनजाति के लोगों की सामाजिक-आ थक स्थिति में आं शक वकास हुआ है।

1. परिचय

भारतीय सं वधान के अनुच्छेद 366 (25) में अनुसू चत जनजातियों को "उन जनजातियों या समुदायों या ऐसे जनजातियों या जनजातीय समुदायों के समूहों के रूप में परिभा षत कया गया है जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत इस सं वधान के प्रयोजनों के लए अनुसू चत जनजाति माना जाता है"। एल. पी. वधार्थी के अनुसार जनजाति एक सामाजिक समूह है, जिसमें निश्चित क्षेत्र, सामान्य नाम, सामान्य वंश, सामान्य संस्कृति, एक अंतः संयोजक समूह का व्यवहार , सामान्य वर्जनाएं, व शष्ट सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व और नेताओं में पूर्ण वश्वास और उनके अलग होने में आ थक आत्मनिर्भरता है (वद्यार्थी, 1981)। अनुसू चत जनजातियों से संबं धत लोग अपने आदिम लक्षणों , व शष्ट संस्कृति, भौगो लक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क के शर्मीलेपन और पछड़ेपन के कारण अन्य समुदायों से अलग हैं। ऐतिहा सक रूप से, आजादी के बाद भी, अनुसू चत जनजाति के लोग व भन्न लाभों से वं चत रहें हैं और यह भारतीय सं वधान में भी अच्छी तरह से माना गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार की सबसे बड़ी चुनौती अनुसू चत जनजाति आबादी के लए सामाजिक आ थक स्थिति में सुधार करके सामाजिक न्याय का प्रावधान है। जनजातीय आबादी भारत की जनसंख्या के सबसे कमजोर वर्ग

को पारिस्थितिक, सामाजिक-आ र्थक और शै क्षक पहलुओं से जोड़ती है। वे मुख्य रूप से राष्ट्र में व्यापक गरीबी का एक बड़ा हिस्सा हैं। इसका कारण यह है क वे सदियों से कई नागरिक सु वधाओं से शो षत और व्यावहारिक रूप से वं चत हैं। ब्रिटिश सरकार ने कस्बों और गांवों में आदिवासी आबादी के उत्थान के लए कुछ सु वधाएं प्रदान कीं जैसे क शक्षा , परिवहन, संचार, च कत्सा आदि। ले कन ये सु वधाएं अपर्याप्त थीं और मुख्य रूप से निहित स्वार्थ के साथ थीं। हालाँ क स्वतंत्रता के बाद सरकार ने उनके उत्थान के लए कई कदम उठाए हैं और उन्हें वकास की मुख्य धारा में जोड़ा है। 2011 की अनुसूची में भारत की सबसे हा लया जनगणना के अनुसार जनजातियों में 8.6 जनसंख्या शा मल है।

2. भारत में अनुसूची क्षेत्र

भारत की कुल जनजातीय आबादी 8.6 प्रतिशत है (भारत की जनगणना, 2011)। भारत में 550 से अ धक आदिवासी समुदाय निवास कर रहे हैं , जिनमें से 75 को आदिम जनजाति समूह के रूप में घो षत कया गया है जो पूरे देश में फैले हुए हैं। आदिवासी आबादी की पहचान हमारे देश के मूल निवा सयों के रूप में की जाती है। उन्हें भारत के लगभग हर राज्य में देखा जाता है। सदियों से , वे प्राकृतिक वातावरण के आधार पर एक साधारण जीवन जी रहे हैं और अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण के लए सांस्कृतिक स्वरुप वक सत कया है। ऐसे आदिवासी समूहों के संदर्भ प्राचीन काल में रामायण और महाभारत काल के साहित्य में भी मलते हैं।

राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसू चत जनजातियों का प्रतिशत, भारत (1981-2011)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र				
असम	-	12.82	12.4	12.4
मणिपुर	27.3	34.41	34.2	35.1
मेघालय	80.58	85.53	85.9	86.1
नागालैंड	83.99	87.7	89.1	86.5
त्रिपुरा	28.44	30.95	31.1	31.8
अरुणाचल प्रदेश	69.82	63.66	64.2	68.8
सिक्किम	23.27	22.36	20.6	33.8
मिजोरम	93.55	94.75	94.5	94.4
उत्तरी				
हिमाचल प्रदेश	4.61	4.22	4	5.7
उत्तर प्रदेश	0.21	0.21	0.1	0.6
केंद्रीय				
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	22.97	23.27	20.3	21.1
पश्चिमी				

गुजरात	14.22	14.92	14.8	14.8
महाराष्ट्र	9.19	9.27	8.9	9.4
राजस्थान	12.21	12.44	12.6	13.5
दादरा और नगर हवेली	78.82	78.99	62.2	52
गोवा	0.99	0.03	0	10.8
दमन और दीव	-	11.54	6.3	6.3
दक्षिणी				
आंध्रप्रदेश	5.93	6.31	8.8	6.3
केरल	1.03	1.1	1.1	1.5
कर्नाटक	4.91	4.26	6.6	7
तमिलनाडु	1.07	1.03	1	1.1
द्वीप				
अण्डमान और निकोबार	11.85	9.54	8.3	7.5
लक्षद्वीप	93.82	93.15	94.5	94.8

स्रोत: जनगणना रिपोर्ट 2011

समाज में प्रमुख समस्या यह है क जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता बहुत कम या अनु चत है। सरकार ने अनुसू चत जनजाति के लोगों के लए कई लाभकारी योजनाएँ शुरू की हैं , ले कन जागरूकता की कमी के कारण , ये योजनाएँ उन तक नहीं पहुँच पाएंगी । समाज में आय और स्थिति के अनु चत स्रोत के कारण, यहां तक क बैंक इन लोगों को ऋण सु वधा प्रदान करने में संकोच करते हैं। भारत के आदिवासी समुदायों के संदर्भ में आ र्थक समस्याओं पर वशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उपलब्ध शोध अध्ययन बताते हैं क जनजातीय आबादी का व शष्ट स्वास्थ्य, पागलपन की स्थिति, अज्ञानता, इन् वजहों से अनुसू चत जनजाति के लोग कुपोषण और संक्रमण रोगों के तहत "गरीबों की बीमारियों " का बोझ उठाते हैं। वे मुख्यधारा के द्वारा नियंत्रित , दबाये हुए और शो षत हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसू चत जनजातियों के पास बुनियादी सु वधाओं की कमी है और राज्य में आदिवासी लोगों के व भन्न पहलुओं से संबं धत समस्याएं हैं जैसे की सामाजिक , आ र्थक , शै क्षक, स्वास्थ्य, धर्म, कानून और व्यवस्था की स्थिति, स्व-केंद्रित प्रवृत्ति और इसी तरह की अनेक समस्याएँ हैं , और उन्हें सरकार से अल्प सु वधाएं मलीं, क्यों क सरकारी योजनाएं आमतौर पर औसत जिले या गांव के लए वक सत या बनायीं जाती हैं , जो वास्त वकता से सम्बं धत नहीं है जब अनुसू चत जनजातियों के सम्बन्ध में बात की जाती है।

3. अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध का उद्देश्य व भन्न सरकारी योजनाओं के तहत मधुबनी जिले के अनुसू चत जनजाति के लोगों की सामाजिक-आ र्थक स्थिति का आकलन और अध्ययन करना और व भन्न योजनाओं के तहत बैंकों द्वारा अनुसू चत जनजाति के लोगों के लए प्रदान की गई वत्तीय सहायता का आंकलन करना है। क्यो क आमतौर पर यह देखा गया है की सरकारी योजनायें केवल कागज के पन्नो में समट के रह जाती है और अनुसू चत जनजातियों तक पहुँच भी नहीं पाती है। इसका एक मुख्य कारन अ शक्षा और जनजातियों के मध्य जानकारी का आभाव है।

4.शोध प्रा व ध

इस शोध का मुख्य उदेश्य मधुबनी जिले में अनुसू चत जनजाति के सामाजिक और आ र्थक स्थिति का आंकलन करना है और वकासखंड का चुनाव अध्धयन क्षेत्र के रूप में कया गया है। व भन्न शासकीय योजनाओं से अनुसू चत जनजाति के लोगों की आ र्थक और सामाजिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन के बारे में पथ्मिक आंकड़ों के संकलन हेतु एक स्व-संर चत प्रश्नावली तैयार की गयी तथा अध्धयन क्षेत्र के 100 अनुसू चत जनजाति परिवारों का चुनाव सु वधा प्रतिचन प्रणाली के माध्यम से अध्धयन के प्रतिचयन के रूप में कया गया। व भन्न सरकारी योजनाओं के कारण उनकी सामाजिक-आ र्थक स्थिति में बदलाव का आकलन करने के लए प्रतिचायनित परिवारों के मध्य साक्षात्कार आयोजित करके प्राथ मक समंको का संकलन कया गया है। एकत्र कए गए समंकों को 21.0 में सारणीबद्ध कर वश्लेषण कया गया है।

ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 10, Issue 3, March 2020 Impact Factor 5.132 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

5. समंको का वश्लेषण

ता लका 1: उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय वर्णन

विवरण		आवृत्ति	प्रतिशत
लिंग			
	पुरुष	64	64
	महिला	36	36
आयु			
	20 साल से कम	12	12
	21–30 वर्ष	51	51
	31–40 वर्ष	16	16
	41–50 वर्ष	11	11
	50 वर्ष से ऊप	10	10
शिक्षा			
	अशिक्षित	42	42
	प्राथमिक	30	30
	10वीं तक	19	19
	12वीं तक	7	7
	स्नातक स्तर	2	2
व्यवसाय			
	कृषि	83	83
	निजी कर्मचारी	5	5
	दैनिक मजदूर	10	10
	अन्य	2	2
आय			
	रु 5000 से कम	30	30
	रु 5, 001 – 10, 000	44	44
	रु 10, 001 – 15, 000	16	16
	रु 15, 001 से अधिक	10	10

ता लका 1में प्रतिचायानित उत्तरदाताओं का जनसांख्यिकीय वर्णन प्रस्तुत कया गया। यह पाया गया क उत्तरदाताओं में से अ धकांश पुरुष (64) थे, जब क महिला उत्तरदतायें लगभग 36 है, जो की पुरुष वर्ग के

प्रभुत्व को दर्शाता है । यह देखा गया क उत्तरदाताओं का 5121-30 वर्ष की आयु वर्ग है, उत्तरदाताओं का 1631 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में आता है, उत्तरदाताओं का 1220 वर्ष से कम आयु वर्ग के अंतर्गत आता है, 11 उत्तरदाताओं की आयु 41-50 आयु वर्ग के हैं , 10 उत्तरदाता 50 वर्ष आयु के ऊपर से हैं। उत्तरदाताओं को योग्यता के अनुसार पांच श्रे णयों में वर्गीकृत कया गया है , प्राथ मक, 10 वीं, 12 वीं, स्नातक और अ श क्षत। ता लका 1 के अनुसार उत्तरदाताओं का 42 अंश निरक्षर स्तर पर है , 30 उत्तरदाताओं ने अपना प्राथ मक वद्यालय स्तर पूरा कर लया है। उत्तरदाताओं के 19 ने अपना 10 वीं पूरा कर लया है , उत्तरदाताओं के 7 ने अपना 12 वीं स्तर पूरा कर लया है और डग्री स्तर पर उत्तरदाताओं का स्तर केवल 2 है। यह भी पाया गया क उत्तरदाताओं का 83 कृ ष व्यवसाय हैं , उत्तरदाताओं का 10 दैनिक वेतन श्रेणी में आता है , उत्तरदाताओं का 5 निजी कर्मचारी हैं, 2 उत्तरदाता अन्य श्रेणी के हैं। यह भी पाया गया क 30 उत्तरदाताओं की मा सक आय 5,000 से नीचे , 44 उत्तरदाताओं की मा सक आय रुपये 5001-10000 के बीच है, 16 उत्तरदाताओं की मा सक आय 10001-15000 है, और केवल 10 उत्तरदाताओं की मा सक आय सीमा 15001 रुपये से ऊपर है।

तालिका 2: अधिग्रहित भूमि का आकार

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1 एकड़ से कम	30	30
2 से 3 एकड़	53	53
3 से 4 एकड़	10	10
4 एकड़ से ज्यादा	7	7

उपरोक्त ता लका से यह स्पष्ट है क उत्तरदाताओं में से 53.0 प्रतिशत के पास 2 से 3 एकड़ भू म है, 30.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास 1 एकड़ से कम भू म है और 10.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं के के पास 3 से 4 एकड़ भू म है। केवल 7.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास 4 एकड़ से अ धक है।

तालिका 3: सरकार से वित्तीय सहायता योजनाएं

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	90	90
नहीं	10	10

ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 10, Issue 3, March 2020 Impact Factor 5.132 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

उपरोक्त ता लका से पता चलता है क 90 उत्तरदाताओं को बैंकों से व भन्न सरकारी योजनाओं के तहत वत्तीय सहायता मली है, जब क 10 उत्तरदाताओं को उपलब्ध सरकारी योजनाओं के तहत बैंक से कोई वत्तीय सहायता नहीं मली है।

तालिका 4: वित्तीय संस्थानों का विवरण

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
को–ऑपरेटिव बैंक	53	53
निजी बैंक	17	17
एसबीआई और राष्ट्रीयकृत बैंक	24	24
अन्य संस्थान	6	6

उपरोक्त ता लका से पाया गया क 53.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं को सहकारी बैंकों से तथा 24.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं को एसबीआई और राष्ट्रीय कृत बैंक से ऋण प्राप्त हुआ है , 17.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने निजी बैंक से ऋण प्राप्त कया है और 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं को एनी बांको से ऋण प्राप्त हुआ है।

तालिका 5: ऋण का उद्देश्य

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
स्व रोजगार	7	7
कृषि	85	85
व्यापार	5	5
अन्य लोन	3	3

उपरोक्त ता लका से, यह पाया गया क 85% उत्तरदाताओं ने कृ ष उद्देश्यों के लए बैंक से ऋण लया है, वहीं 7% उत्तरदाताओं ने स्वरोजगार के लए , 5% ने व्यावसायिक उद्देश्य के लए और 3ः उत्तरदाताओं ने अन्य उद्धेश्यों की पूर्ती हेतु ऋण प्राप्त कया है।

6. निष्कर्ष

बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक का चुनाव अध्ययन क्षेत्र के रूप में कर के अनुसू चत जनजाति के लोगों की सामाजिक-आ र्थक स्थिति का अध्ययन करने का प्रयास कया गया है। उपरोक्त प्रस्तुत वश्लेषण से

यह पता चलता है क अनुसू चत जनजाति वर्ग के लोग व भन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक होने लगे हैं और इन योजनाओं का लाभ अपने सामाजिक और आ थक वकास के लए लेना शुरू कर दिया है । कृ ष इन लोगों का प्रमुख व्यवसाय और फसल उत्पादन बढ़ाने के हेतु बेहतर कृ ष उपकरण प्राप्त करने के लए अनुसू चत जनजातियों के लोग व भन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत बैंकों से वत्तीय वत्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं जो की उनके लए काफी मददगार साबित हुई। इन वत्तीय सहायता के कारण लोग अब अपने फसल उत्पादन में वृ द्ध करने में सक्षम होने लगे है , और कृ ष उत्पादन से होने वाले लाभ से अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर कर प् रहें है। बेहतर आ थक स्थिति लोगों के जीवन स्तर के उन्नयन और समग्र वकास की ओर ले जाती है। हालां क उत्तरदाता निरक्षर हैं , वे चाहते हैं क उनके बच्चे सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली शक्षा का लाभ उठाएं। सरकार द्वारा परिवहन सु वधा एवं बस सु वधा भी प्रदान की जाती हैं। इससे पता चलता है क सरकार ने जनजातीय लोगों की परिवहन सु वधा के वकास में बहुत रु च दिखाई है। परिवहन सु वधा के संबंध में , आदिवा सयों के वकास के लए शक्षा और सरकारी उपायों ने अपना महत्व बनाया है और यह जनजातीय लोगों तक पहुँच गया है जो की वास्तव में प्रशंसनीय है। पहले आदिवा सयों को ऋण देने में बैं कंग संस्थान कोई रू च नहीं दिखाते थे पर व भन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गन अब वत्तीय संस्थान भी अनुसू चत जनजातियों को ऋण प्रदान करने लगे हैं। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है की बिलासपुर जिले के कोटा वकासखंड में जनजाति के लोगों की सामाजिक-आ थक स्थिति में एक आं शक वकास हुआ है।

संदर्भ सू च

1. डॉ. वरियर एल्विन स मति (1960) ‘‘आदिवासी वकास कार्यक्रमों पर अध्ययन दल की रिपोर्ट‘ , भारत सरकार नई दिल्ली एओ, स मति
2. रॉय बर्मा (1978), ‘‘भू म अलगाव की भावना-ए जनजातीय अर्थव्यवस्था जनजाति, वॉल्यूम, एक्स, संख्या 4, 1978।
3. फेंडर थाकर (1986), ‘‘भारत में जनजातियों का सामाजिक-आ थक वकास‘‘ , दीप और दीप पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1986।
4. कुन्हामन, एम. (1982), ‘‘ केरल की जनजातीय अर्थव्यवस्था: एक अंतर प्रतिगामी वश्लेषण‘‘, नई डी, 1982।
5. दुल्ज (1962), ‘‘केरल के जनजाति फरतिया सेवा शहरा ‘‘, 1992।
6. बख्शी और करण बेलर (2000), ‘‘सामाजिक और अनुसू चत जनजातियों के आ थक वकास‘‘, दीप और दीप प्रकाशन प्राइवेट ल मटेड। नई दिल्ली, 2000

7. शर्मा. ए. एन (2002), आदिवासी कल्याण और वकास, अरूप एंड संस, नई दिल्ली।
8. डॉ. सुजाता कन्नूगो (2010), ट्राइबल , मोहित प्रकाशन, नई दिल्ली के बीच वकास कार्यक्रम और सामाजिक परिवर्तन ।
9. सुरेश के शर्मा (2010), "ट्राइब्स बाय द एज", वस्टा इंटरनेशनल पब्लि शंग हाउस, नई दिल्ली।
10. पीके भौ मक (2005), "आदिवासी और सतत वकास", कल्पना प्रकाशन, नई दिल्ली।